(क) क्या यह सच है कि नक्सल प्रभावित राज्यों में, पिछले कुछ वर्षों में पुलिसकर्मियों की संख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों के कारण, पुलिसकर्मियों के लिए अपेक्षित संख्या में आवास गृहों का निर्माण नहीं कर पा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस कर्मियों के लिए पृथक से आवासीय योजना के लिए स्वीकृति प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क): जी, हां । नक्सल प्रभावित राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में राज्य पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।**

**(ख) से (घ): केन्द्रीय सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य पुलिस कर्मियों के लिए रिहाइशी आवास के निर्माण हेतु वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । गृह मंत्रालय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) के लिए एक योजनेतर स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए रिहाइशी भवनों का निर्माण शामिल है । राज्य सरकारें भी सुरक्षा बलों को आवास उपलब्ध कराने के लिए स्वयं अपनी योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं ।**